

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-2464 / 2023

मीनाक्षी सैनी

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक(अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
4. प्रभारी अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडीपाल कला ब्लॉक बांदीकुई जिला दौसा।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 29.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 15.09.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी की नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी को नवीन पदोन्नति पद पर उप जिला चिकित्सालय, मण्डावरी, दौसा पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सबसेंटर नन्देरा, बान्दीकुई, दौसा में कार्यरत है। पदोन्नति उपरांत विभाग द्वारा विकल्प पत्र मांगे जाने पर अपीलार्थी द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया था, परंतु अपीलार्थी को उसके द्वारा दिये गये विकल्पों में इच्छित स्थान पर पदस्थापन नहीं कर अन्य स्थान पर पदस्थापन कर दिया गया जो उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण पदोन्नति उपरांत विकल्प पत्र में भरे गये इच्छित स्थानों पर नहीं किया गया है। नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेता है। केवलमात्र विकल्प पत्र दिये जाने के आधार पर अपीलार्थी को यह

अधिकार उत्पन्न नहीं होता है कि वह विकल्प पत्र वाले स्थान पदस्थापन प्राप्त करने का अधिकारी है।

4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

5. उपरोक्त प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)